

प्रारूप-5

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत बिनवालगाँव-कलियाधुरा (छीड़ाखान) मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई : 15.200 कि०मी०)

उपरोक्त परियोजना की स्वीकृति शासनादेश संख्या 764/।।। (2)/08-85(प्रा०आ०)/2007 दिनांक 24-03-2008 के द्वारा प्राप्त हुई है। जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का शासनादेश संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
प्रालीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत

अधिसासी अभियन्ता
अधिसासी अभियन्ता
प्रालीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत

संख्या- 764 / 111 (2) / 08-05 (प्र(0800) / 2007

प्रेषक

मदीप सिंह रावत,
राम सचिव,
राज्यराज्यपंड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

तत्प्राप्त
श्रीमती निवा
27/03/08

प्रमुख चम्पावत
विनवालाव श्र कलियाधु

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय- वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य योजना के अन्तर्गत 181 कार्यों के निर्माण की प्रशासकीय वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2008

उपरोक्त विषयक मुख्य अभियन्ता स्तर-2 लोक निर्माण विभाग, पीडी/ अरमोडा एवं आनके द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये आगणनों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध कराये गये 181 कार्यों के आगणन लागत रु० 22496.12 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 22219.77 लाख (रुपये दो सौ बाईस हजार नब्बे सौ लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणनों की उनके सामुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सामुख कालम-08 में अंकित रु० 0.05 लाख विवरणानुसार कुल रु० 9.05 लाख (रुपये नौ लाख पाँच हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन साहस स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दर शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ही गई हो, की स्वीकृति निम्नानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का मुग्तान नियमानुसार प्रथम वसियता के आधार पर किया जाय एवं भूदान की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र तैयार कर नियमानुसार तालम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
- युक्तमुक्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- कार्य कराने से पूर्व जलवायु और आर्किटेक्चर तर्जनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुसार ही कार्यों को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निदेशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुसार कार्य किया जाय।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- उक्त कार्य पर इसके किसी भाग हेतु यदि इसके पूर्व किया या अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो सक्षम धनराशि का आहरण न करके शासन को सूचित

कार्य प्रारम्भ के लिये

तत्प्राप्त

सहायक अभियन्ता
पि० ए०, लो० नि० वि०,
चम्पावत

A-2.2

#-2,2

Office of the
D No 1065
File No 320
Date 31/1/75
Ex. Engr LNV

उपयुक्त पायी जाते

-2-

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोजनशाला से टैस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी प्रौद्योगिकों हेतु भूमि का अन्वेषण कर के कब्जा लेने के साथ ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस क्षेत्रका हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।
13. यदि उक्त कार्यो मे से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को सौंपित कर दी जायेगी।
14. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य दृष्टांतों आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के अनुमानों/पुनरीक्षित आंकड़ों पर पञ्चायती एवं वित्तीय अनुमान के साथ-साथ विस्तृत आंकड़ों पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का निम्नांक-31.03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य करता समय टैंडर नियमक नियमों का भी अनुपालन किया जाय, यदि टेण्डर करने में कार्य प्रारम्भ होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाता है तो उसे समाप्त कर देना होगा।
15. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/प्रौद्योगिक प्रगति निवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त आयुक्त की जायेगी।
16. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिवक्तासी अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
17. इस संदेश में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-805A सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिवार-04 जिला तथा ग्राम्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सरकार -02 गंगा निर्माण कार्य-24 ग्रहण निर्माण कार्य के नामे ऊँटा जायेगा।
18. यह आदेश वित्त, अनुमान-2 के अशासकीय सचिया-यू.ओ.-388/XXVII(2)/2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।
- सलग्नक-101 कार्यों की सूची।

भवदीय
 चन्द्र प्रदीप सिंह
 (प्रदीप सिंह राजा)
 उप सचिव।

संख्या- 764 (1) / 111-2 / भा.प्र.वि.नांक ।

1. भालखण्ड (संघ प्रथम), ओवरलैण्ड मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट, मॉडर्न देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल पौड़ी / नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर-2 लोनिचि पौड़ी / अल्मोड़ा।
5. दरिल कोषाधिकारी, देहरादून।
6. उत्तराखण्ड अभियन्ता, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. चित्त अनुपम-2, चित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुपम-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गई मुक।

कोटो प्रति प्रमाणित
होया प्रति सत्यापित
Jr
सहायक अधिवक्ता
सहायक अभियंता
मार्ग विभाग, ली० नि० बि०,
चम्पावत (उत्तराखण्ड)
A.Padley

आज्ञा से
१७ मी. ८०० मी.
(प्रतीप दि. १५.११.१९५०)
उप. म. वि. प्र.

U(1) (1429) / 148 EA - 3 / 0.8 1.028 / 3 / 8

ਅੰਤਿਮੀਂ ਸਮੇਂ ਆਈ ਆਤਮਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਕਾਇਦਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ

119	मार्ग का निर्माण (बानसी से पहनिया)	2.950	30.38	30.38	0.05
120	खटीमा के अन्तर्गत बिरिया चौहरी से मशीला बेलघाट तक मार्ग का पुन निर्माण कार्य ।	3.00	72.75	72.75	0.05
121	खटीमा के अन्तर्गत टनकपुर मार्ग से अमाऊ प्रान्त तक मार्ग का पुन निर्माण एवं सुधार	1.50	23.94	23.94	0.05
122	खटीमा के अन्तर्गत गुरुखड़ा चन्देरी मार्ग का पुन निर्माण एवं सुधार कार्य ।	2.60	41.50	41.50	0.05
123	खटीमा के अन्तर्गत भकरपुर पौरिया मार्ग का पुन निर्माण एवं सुधार कार्य ।	3.00	47.88	47.88	0.05
124	खटीमा के अन्तर्गत प्रतापपुर नं 4 से पार खमरिहा तक मार्ग का निर्माण कार्य ।	3.00	72.75	72.75	0.05
125	ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत भूसाही सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग का गुन्नाही-छतरपुर मार्ग तक सुदृढीकरण कार्य ।	0.550	16.60	15.13	0.05
126	पिथौरागढ़ में दलुवाकोट की लोक गागरा से गैरा गौंस तक मार्ग का नव निर्माण कार्य ।	5.00	183.75	183.75	0.05
127	पिथौरागढ़ में कालिका खुमती मोटर मार्ग से पन्ना गौंस गैरबसोरा अमगला एवं लिडवा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।	4.00	147.00	147.00	0.05
128	पिथौरागढ़ में संगीठ दशौली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य ।	1.00	36.75	36.75	0.05
129	पिथौरागढ़ में रणकोट महाकाली मंदिर होते हुए गंगोलीहाट बाई पास मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।	5.00	183.75	183.75	0.05
130	पिथौरागढ़ में तौरगाड़ में पैदल स्टील गार्डर सेतु का निर्माण कार्य ।	35.00	66.96	66.96	0.05
131	पिथौरागढ़ में पक्काधार-नैनी-जगेश्वर बाया रोरागाड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।	7.500	275.63	275.63	0.05
132	पिथौरागढ़ में गुनस्थारी में बल्लोगाड़ बला से दाफा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।	6.00	220.50	220.50	0.05
133	पिथौरागढ़ में सैणराही से होकरा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।	15.00	551.25	551.25	0.05
134	चम्पावत में बिगवालागवि से कलियाधुरा (छोडाखान) मोटर मार्ग का निर्माण सेतुओं सहित ।	16.500	671.73	671.73	0.05
135	ऊधमसिंह नगर में ग्राम महाराजपुर से कनकपुर लिंक मार्ग का पुनरोद्धार कार्य ।	2.50	70.00	70.00	0.05
136	ऊधमसिंह नगर में छतरपुर डींग कालोनी की हाथिप्रस्त मार्ग का पुन निर्माण कार्य ।	0.800	13.89	13.75	0.05
137	ऊधमसिंह नगर में राउहोका शक्तिफार्म से अरुन्ध नगर की ओर सड़क निर्माण कार्य ।	2.00	83.95	67.61	0.05
138	ऊधमसिंह नगर में शक्तिफार्म मार्ग चुंगी से मुख्य मार्ग धोरगलिया हल्दानी सिडकूल मार्ग	0.60	14.00	14.00	0.05

20 मी 100 मी

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
प्रकाश चम्पावत

(रु० नौ लाख पाँच हजार मात्र)

(પ્રવીણ સિંહ રાવલ)

सहायक अभियंता
ग.खं०, लो०नि०वि०,
चम्पावत

ਪ੍ਰਾਪਤਕ੍ਰਮ-36ਜ਼ 20 ਮਾਰਚ '87 ਵਿਚ 27.3.00

सहायक अभियन्ता
स्थीय खण्ड, लो० नि० वि
सम्प्रदाय, (उत्तराखण्ड)

[illegible]

पृष्ठ ११ मुद्रण अभियन्ता प्रसार ३/१४
लोक निर्माण विभाग

संख्या:-जी0आई0:-1863 /7-1-2009-800(2050)/2007

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 27-1-2009.

विषय:- जनपद-चम्पावत के अन्तर्गत रीठा-बिनवालगौव-मिडार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.00 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:-1840/1जी-2080 (चम्पा0) दिनांक 24-01-2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-चम्पावत के अन्तर्गत रीठा-बिनवालगौव-मिडार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.00 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/02/2008/एफ.सी./1695 दिनांक 19-01-2009 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा 6.00 हे० अवन्त सिविल एवं सोयम वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका रख-रखाव किया जायेगा। प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण सिविल एवं सोयम वन भूमि पर प्रस्तावित नहीं किया गया है, अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल एवं सोयम वन भूमि चयनित कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना शासनादेश निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत द्वारा नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसे नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।
3. राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-V-06/XVIII(1)/2009 दिनांक 09-01-2009 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वैज्ञानिक प्रबन्धन की दृष्टि से वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति की शर्त संख्या-2 में यह शर्त अधिरोपित की गई है कि उक्त सिविल भूमि का प्रशासनिक नियंत्रण छः माह के अन्तर्गत वन विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा व यदि उक्त अवधि में इस भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा व यदि प्रदत्त विधिवत स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। भारत सरकार की उक्त शर्त के अनुपालन में जिलाधिकारी, चम्पावत द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि को राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन के उक्त आदेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित किया जायेगा व इसकी सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी।
4. लोक निर्माण विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगा और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो वन विभाग द्वारा निर्धारित निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा।

सहायक अभियंता
प्र.खं०, लो०नि०वि०,
चम्पावत

6. उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि लो विभाग को उसकी उचित प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि लोक निर्माण विभाग को अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि भाग, जो लोक निर्माण विभाग के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकार वापस हो जायेगी।
7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. वन विभाग तथा उसके अधिकारियों को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हरतान्तरि गृहखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
9. लोक निर्माण विभाग के ध्य पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त यथोचित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं रख-रखाव किया जायेगा।
10. लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किया जायेगा।
11. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
12. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित प्राणों की स्थानीय जनता के हक-हकूक के दृष्टिगत जायेगा।
13. लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक प्रभाव को कम किया जा सके।
14. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की भूमि से सड़क निर्माण मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. मार्ग निर्माण के दौरान न्यूनतम आवश्यक वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
16. प्रयोजन एजेन्सी से एकत्रित एनओपीओ एवं क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की धनराशि को तदर्थ क्षतिपूर् वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
17. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलबे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dampin Sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।
2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं०-104/28/प्र०स०-आ०व०मा०वि० दि०-1-1-2001, कार्यालय ज्ञाप सं०-4-41-2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 3-2-1977 द्वारा प्रदेत अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या:-जी०आई०:-1863/7-1-2009-600(2050)/2007 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन सारक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, रीक्टर-एच, पंचग ताल, अलीगंज, लखनऊ।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महासंचालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. जिलाधिकारी, चम्पावत।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
7. अधिशारी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रमुख, लो०नि०वि०
वित्त विभाग, उत्तराखण्ड

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)